पंजाब सरकार

हरपाल सिंह चीमा

वित्त मंत्री, पंजाब

द्वारा

पंजाब विधान सभा में

वर्ष 2026-27 का

बजट पेश करते समय दिया गया

भाषण

8 मार्च, 2026

चण्डीगढ़

बजट 2026-27

वित्त मंत्री

हरपाल सिंह चीमा

का भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. मैं आज विनम्रतापूर्वक आम आदमी पार्टी सरकार का पांचवां बजट पेश करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, और इस पल की जिम्मेदारी से पूरी तरह अवगत हूं। चार साल के पूरे कार्यकाल के बाद, यह बजट ऐसे चरण में पेश किया जा रहा है जहां शब्दों से ज्यादा किए गए काम मायने रखते हैं, और जहां शासन को अपने आप में बोलना चाहिए। इसे इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष विनम्रता के साथ और किए गए कार्यों से प्राप्त आत्मविश्वास के साथ रखा जा रहा है, और हम इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि शासन की वास्तविक कसौटी ठोस परिणाम और हमारे नागरिकों के दैनिक जीवन के अनुभव हैं।

2. पंजाब ने कभी भी अन्याय को चुपचाप स्वीकार नहीं किया। यह शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने हमें सिखाया कि वास्तविक आज़ादी केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में गरिमा, समानता और न्याय है। जब मार्च 2022 में पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया, तो उन्होंने उसी भावना के साथ ऐसा किया - खोखली राजनीति को ठुकराते हुए और ऐसी सरकार की मांग करते हुए जो इरादे में ईमानदार, संकल्प में दृढ़ और कार्रवाई में निर्णायक हो। एक रंगला पंजाब का

हमारा दृष्टिकोण इसी नैतिक नींव से उभरा है।

3. बजट पर बात करने से पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रहूंगा यदि मैं विनाशकारी बाढ़ के दौरान पंजाब के लोगों द्वारा दिखाए गए साहस और दृढ़ता को स्वीकार नहीं करता, जिसने हमारे राज्य की परीक्षा ली थी। जब घर जलमग्न हो गए और आजीविका बाधित हो गई, तो पंजाब के लोग उल्लेखनीय ताकत और करुणा के साथ एक साथ खड़े रहे, एक-दूसरे की मदद की और धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। सरकार ने प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर राहत प्रदान करने, आवश्यक सेवाओं को बहाल करने और पुनर्वास में तत्परता और संवेदनशीलता के साथ सहायता करने का कार्य किया। इस प्रतिष्ठित सदन की ओर से, मैं अपने नागरिकों, स्वयंसेवकों और अधिकारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने अवसर की माँग पर खरा उतरते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि प्राकृतिक आपदाएँ भले ही कठिनाई पैदा करें, लेकिन वे हमारे लोगों की भावना को कभी कमजोर नहीं कर सकतीं।

4. माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के करुणामय नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रही। तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने नागरिकों को हुए नुकसान, जिसमें फसलों, घरों और पशुधन को हुई क्षति शामिल है, के लिए सबसे अधिक मुआवजा पैकेजों में से एक की घोषणा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुआवजा रिकॉर्ड समय में जारी किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रभावित परिवारों को सबसे अधिक जरूरत के समय

समय पर सहायता मिले। यह हर चुनौती में पंजाब के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यह सुनिश्चित करता है कि मुश्किल घड़ी में कोई भी नागरिक अकेला महसूस न करे।

5. आज का बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो महिलाओं की शक्ति, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए समर्पित दिन है। पंजाब की बेटियों ने राज्य और देश को अत्यधिक गौरवान्वित किया है – चाहे फ़िर वह खेल हो, विज्ञान हो, कला हो या सार्वजनिक जीवन। हरमनप्रीत कौर जैसी महान खिलाड़ी उस साहस, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पंजाब की बेटियों को परिभाषित करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक सुधार उनकी आकांक्षाओं से प्रेरित हैं और उनके सम्मान, सशक्तिकरण और खुशी के लिए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से हैं। यह बजट पंजाब की माताओं और बेटियों को समर्पित है - जो उनकी शक्ति को एक श्रद्धांजलि और हमारे समाज तथा हमारे भविष्य में उनके अमूल्य योगदान का उत्सव है।

6. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की जिम्मेदारी संभालने के पहले दिन से ही, सरदार भगवंत सिंह मान जी के सक्षम नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने संकल्प लिया था कि लोगों को दी गई गारंटियाँ महज कागज़ों में कैद नहीं रहेंगी। वे स्वयं शासन का मार्गदर्शन करेंगे - हमारे बजट को आकार देंगे, हमारी प्राथमिकताओं को परिभाषित करेंगे और हमारी जवाबदेही का निर्धारण करेंगे। मैं अत्यधिक गर्व के साथ इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष यह कहना चाहता कि शायद ही कभी कोई सरकार, अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष में,

यह कह पाई हो कि पंजाब के लोगों से किया गया हर वादा आत्मविश्वास और भरोसे से पूरा किया हो। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये वचन केवल आश्वासन नहीं थे, बल्कि संरचित नीतिगत हस्तक्षेप थे, जो बजटीय समर्थन, संस्थागत सुधार और मापने योग्य परिणामों द्वारा समर्थित थे। इसीलिए मैं इस बजट का नाम "सारी गारंटियाँ पूरी करन वाला बजट" रख रहा हूँ।

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गारंटियों का प्रभाव हमारे लोगों के दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। राज्य भर में लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल ने लाखों परिवारों को निरंतर वित्तीय राहत प्रदान की है। लंबे समय से सुलभ स्वास्थ्य सुविधा से वंचित परिवारों के लिए, आम आदमी क्लीनिकों ने उनके घरों के नजदीक मुफ्त परामर्श, दवाएं और जांच उपलब्ध कराकर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तक पहुंच को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसके अलावा, पिछले बजट में आश्वासन दिए जाने के अनुरूप, सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। यह प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि किसी भी नागरिक को आवश्यक चिकित्सा उपचार और वित्तीय स्थिरता के बीच चयन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।

8. शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल ऑफ एमिनेंस के माध्यम से सरकारी स्कूलों का परिवर्तन एक स्पष्ट संदेश देता है — कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सार्वजनिक गारंटी होनी चाहिए, न कि कोई निजी विशेषाधिकार। साथ ही, मुख मंत्री तीर्थ यात्रा योजना जैसी पहलों ने एक ऐसे शासन दर्शन को प्रतिबिंबित किया है जो आस्था का सम्मान करता है, वरिष्ठ नागरिकों

का आदर करता है, और पंजाबी समाज के भावनात्मक और सांस्कृतिक ताने-बाने को पहचानता है। व्यवहार में एक जन-केंद्रित सरकार ऐसी ही होनी चाहिए।

9. माननीय अध्यक्ष महोदय, उन चुनौतियों के बारे में स्पष्ट रूप से बात करना भी आवश्यक है जो हमें विरासत में मिली थीं। जब यह सरकार सत्ता में आई, तो पंजाब के सामने नाजुक सार्वजनिक वित्त, कमजोर जनता का विश्वास और नशीली दवाओं का बढ़ता खतरा था, जिसने एक पूरी पीढ़ी को खोखला करने की धमकी दी थी। हमने आंखें मूंद कर नहीं बैठे। अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, बेहतर राजस्व संग्रह और व्यय के युक्तिकरण के माध्यम से, हमने कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं की रक्षा करते हुए वित्तीय स्थिरता बहाल करने का काम किया है।

10. साथ ही, नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा गया है - गहरी जड़ें जमा चुके राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ को तोड़कर, प्रवर्तन को मजबूत करके, नशा मुक्ति और पुनर्वास के प्रयासों का विस्तार करके, और यह स्पष्ट करके कि पंजाब के युवाओं के भविष्य को आत्मसमर्पण नहीं किया जाएगा। यह लड़ाई कठिन ज़रूर है, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

11. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार का यह पांचवां बजट हमारी शासन यात्रा में एक निर्णायक क्षण का प्रतीक है। यह पिछले चार वर्षों की उपलब्धियों को समेकित करता है और पंजाब की प्रगति के अगले चरण के लिए दिशा निर्धारित करता है। अब ध्यान सुधारों को और बेहतर बनाने, सेवा वितरण को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर

है कि पिछले चार वर्षों में रखी गई नींव राज्य के लिए टिकाऊ और समावेशी विकास में परिवर्तित हो। यह पंजाब के लोगों के लिए एक नई मिसाल भी स्थापित करता है कि केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही जनता से की गई हर गारंटी को पूरा करती है – जबकि अन्य पार्टियों ने 75 वर्षों तक केवल उन्हें बेवकूफ बनाया है और पंजाब को लूटा है। इसी विश्वास और जिम्मेदारी की स्पष्ट भावना के साथ, अब मैं इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

बजट वित्त वर्ष 2026-27

माननीय अध्यक्ष महोदय,

12. पंजाब की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक वर्ष में निरंतर लचीलापन और संरचनात्मक स्थिरता प्रदर्शित की है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹8,91,487 करोड़ अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के ₹9,80,635 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिसकी प्रत्याशित वृद्धि दर 10 प्रतिशत है। इसे बेहतर कृषि उत्पादकता, विस्तार करती सेवा गतिविधियों और मजबूत औद्योगिक गति से समर्थन प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय,

13. मैं वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,60,437 करोड़ के बजट व्यय का प्रस्ताव रखता हूँ। प्रभावी राजस्व घाटा जीएसडीपी का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.08 प्रतिशत अनुमानित है। ये अनुमान जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन के

साथ-साथ निरंतर आर्थिक विकास और जन कल्याण के प्रति हमारे संकल्प की पुष्टि करते हैं।

14. जैसे-जैसे हम पंजाब की विकास यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, मैं अब इस गरिमापूर्ण सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रमुख क्षेत्र-विशिष्ट पहलों और आवंटनों को प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक आवंटन सुधारों को करने, पहुँच को व्यापक बनाने और सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के एक सुविचारित प्रयास को दर्शाता है।

शिक्षा

15. माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब में शिक्षा सुधार का किया गया वायदा अब संरचनात्मक बदलाव की ओर बढ़ गया है। पिछले चार वर्षों में, हमने बुनियादी ढांचे के उन्नयन, आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी स्कूल प्रणाली के भीतर उत्कृष्टता केंद्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, यह सुधार यात्रा अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है, अर्थात विस्तार के साथ मज़बूती। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शिक्षा क्षेत्र में ₹19,279 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में 7% की वृद्धि है।

स्कूल शिक्षा

16. माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब का भविष्य कक्षाओं में लिखा जाएगा। दुनिया का हर विकसित राष्ट्र एक निर्णायक नींव पर खड़ा हुआ है, वह है अपने बच्चों को प्रदान की

जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता। यदि पंजाब को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना है, रोजगार सृजित करना है, निवेश आकर्षित करना है और अगली पीढ़ी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करनी है, तो शिक्षा को केवल एक और विभाग नहीं माना जा सकता। यह एक मिशन होना चाहिए। यह शासन का केंद्रबिंदु होना चाहिए। इस सरकार ने यह निर्णय स्पष्टता, दृढ़ विश्वास और साहस के साथ लिया है।

17. पंजाब के पास हमेशा सक्षम लोग, उद्यमशीलता की भावना और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन रहे हैं। जिस चीज की आवश्यकता थी, वह था निर्णायक नेतृत्व। पंजाब सिक्खिया क्रांति के तहत, हमने शिक्षा को राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर रखने और अभूतपूर्व सुधारों एवं निवेशों के साथ इसका समर्थन करने का एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस प्रतिबद्धता के परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार के "परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024" में, पंजाब क्लासरूम लर्निंग के परिणामों में नंबर एक पर रहा, उसने केरल राज्य को भी पीछे छोड़ दिया, जो कई वर्षों से लगातार शिक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों ने प्रदर्शित कर दिया है कि उत्कृष्टता कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार है।

18. राष्ट्रीय नेतृत्व हासिल करने के बाद, अब हम पंजाब की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के लिए तैयार कर रहे हैं। एक निर्णायक उपलब्धि के रूप में, पंजाब सरकार ने अगले 6 वर्षों में 3500 करोड़ रुपये के आवंटन से हमारी शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए सिक्खिया क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। हमने स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व बैंक के

साथ एक ऐतिहासिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पंजाब के इतिहास में शिक्षा सुधारों के सबसे बड़े निवेशों में से एक है। यह मिशन बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को मजबूत करेगा, विज्ञान और वाणिज्य संकायों का विस्तार करेगा, शिक्षकों और स्कूल लीडर्स को सशक्त बनाएगा, संरचित कैरियर परामर्श को संस्थागत रूप देगा और शासन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करेगा। पंजाब केवल स्कूलों में सुधार नहीं कर रहा है। हम अगली पीढ़ी के लिए संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नया स्वरूप दे रहे हैं।

19. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गरिमा, सुरक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचा आवश्यक है। लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में, हमने बुनियादी और उन्नत दोनों मानकों को सुनिश्चित किया है। आज, 99 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी है। 10,095 शौचालयों का निर्माण किया गया है। एक लाख से अधिक नए डेस्क की खरीद से यह सुनिश्चित हुआ है कि कोई भी बच्चा फर्श पर न बैठे। 8,286 सफाई कर्मचारी स्कूलों में दैनिक सफाई सुनिश्चित कर रहे हैं। 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी स्कूल परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। 1,798 कैंपस मैनेजर स्कूल प्रशासन में सहायता कर रहे हैं। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 6,200 कक्षाओं का नवनिर्माण किया गया है और 4,700 का जीर्णोद्धार किया गया है। इस वर्ष, स्कूल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए 690 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस वर्ष का फोकस बड़े पैमाने पर सफेदी और सौंदर्यीकरण अभियान होगा, ताकि हर सरकारी स्कूल गर्व, स्वच्छता और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करे।

20. अध्यक्ष महोदय, हमारे 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस सार्वजनिक शिक्षा को नया आयाम दे रहे हैं। 193 करोड़ रुपये के आवंटन ने पहले ही इन संस्थानों में बुनियादी ढांचे,

प्रौद्योगिकी, फर्नीचर, वर्दी और पेशेवर सेवाओं को मजबूत किया है। परिणाम खुद बयां करते हैं। 2025 में, सरकारी स्कूलों से 267 छात्रों ने जेईई मेन्स और 847 ने नीट योग्यता प्राप्त की। यह 2022 के बाद से लगभग 5 गुना उछाल है! हम छात्रों को सरकारी स्कूलों के भीतर ही संरचित व्यावसायिक तैयारी प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ साझेदारी कर रहे हैं। पंजाब की प्रतिभा अब आय या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेगी। हम यह सुनिश्चित करने के लिए निवेश करना जारी रखेंगे कि हमारे छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो।

21. शिक्षा का लक्ष्य सार्थक भविष्य की ओर ले जाना होना चाहिए। हम कक्षा IX से XII तक के लगभग 7.35 लाख छात्रों को कवर करने वाले एक राज्यव्यापी कैरियर परामर्श ढांचे को संस्थागत रूप दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को नौकरियों और उच्च शिक्षा के निर्णयों के बारे में अधिक जागरूक बनाने के लिए कैरियर परामर्श पोर्टल शुरू करेंगे।

22. शैक्षणिक सुधारों के साथ-साथ, हमने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में एक अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन शुरू किया है। हमने सरकारी स्कूलों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगभग 395 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इस समय, सरकारी स्कूलों में 38,649 डेस्कटॉप कंप्यूटर वितरित किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर लैब हो। इसके अलावा, 3,694 स्कूलों में 8,268 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लगाए जा रहे हैं। यह पंजाब के सरकारी स्कूलों के इतिहास में सबसे बड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे के उन्नयन में से एक है। हम निर्णायक रूप से डिजिटल विभाजन को पाट रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि

सरकारी स्कूल के हर बच्चे की आधुनिक 21वीं सदी के शिक्षण उपकरणों तक पहुंच हो। कुछ लोग केवल आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बात करते हैं, लेकिन हम अपने छात्रों तक तकनीक पहुंचाने में निवेश करते हैं।

23. माननीय अध्यक्ष महोदय, सीखने के परिणामों में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर विश्व बैंक के साथ वैश्विक सहयोग तक, गरिमा-संचालित बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल सशक्तिकरण तक, स्कूल ऑफ एमिनेंस से लेकर संरचित कैरियर मार्गों तक, पंजाब एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि एक पूर्ण शिक्षा परिवर्तन का गवाह बन रहा है। पंजाब की वास्तविक संपत्ति उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी कक्षाओं में है, उसकी सड़कों में नहीं, बल्कि उसके बच्चों के सपनों में है। हम उस भविष्य का निर्माण ईंट-ईंट जोड़ कर, कक्षा दर कक्षा, बच्चा दर बच्चा कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा

24. माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्ञान-आधारित और कुशल पंजाब के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक बना हुआ है। चालू वर्ष के दौरान, सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सुविधाओं और छात्र सुविधाओं में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य किए गए हैं।

25. मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र नाम से एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संस्थान को

मिशन मोड में स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इस घोषणा को वास्तिवक रूप दिया जा सके।

तकनीकी शिक्षा

26. हमारी सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेगी, यह मानते हुए कि एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था को एक प्रशिक्षित और उद्योग-तैयार कार्यबल द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। पिछले वर्ष के दौरान, सरकारी आईटीआई में सीटिंग क्षमता में 35,000 से 52,000 तक महत्वपूर्ण विस्तार किया गया, जिससे राज्य भर के हजारों युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई।

27. इसके अलावा, पंजाब ने 11 जेलों में आईटीआई चालू किए हैं, जिससे कौशल विकास को सामाजिक पुनर्वास के साथ जोड़ा गया है - यह एक अग्रणी पहल है जो कैदियों को प्रमाणित व्यावसायिक कौशल और सम्मानजनक पुन: एकीकरण का मार्ग प्रदान करती है। पीएम-सेतु के तहत हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से, चयनित आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि इनोवेशन लैब और उद्योग साझेदारियां - जिसमें आईआईटी रोपड़ के साथ सहयोग शामिल है - एआई, इंटरनेट आफ़ थिंग्ज़ (आईओटी) और साइबर-फिजिकल सिस्टम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संपर्क को मजबूत कर रही हैं। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 में तकनीकी शिक्षा के तहत पहलों के लिए 569 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

विश्वविद्यालयों और घटक कालेजों को अनुदान सहायता

28. हमारी सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों, जिनमें गडवासु (GADVASU), पीएयू (PAU), पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और उनके संघटक कॉलेज शामिल हैं, की सुदृढ़ीकरण और विकास को प्राथमिकता देती रहेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, इन संस्थानों में शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान उन्नयन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के समर्थन के लिए ₹1,760 करोड़ का बजटीय प्रावधान निर्धारित किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

29. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने राज्य के इतिहास में सबसे व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारों में से एक, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की है, जिसके तहत पंजाब के लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत, पंजाब का हर परिवार 900 से अधिक सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का हकदार है। सरलीकृत प्रक्रियाओं और सेहत कार्ड जारी करने से, उपचार तक पहुंच सहज और पारदर्शी बना दी गई है। वित्त वर्ष 2026-27 में 2,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है, यह योजना लगभग 65 लाख परिवारों को लाभान्वित करने और राज्य भर के परिवारों पर गंभीर चिकित्सा उपचार के वित्तीय बोझ को काफी कम करने वाली है।

30. माननीय अध्यक्ष महोदय, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इस सरकार की प्रतिबद्धता के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना एक आधार स्तंभ बना हुआ है। आम आदमी क्लिनिक पूरे पंजाब में डोरस्टेप हेल्थकेयर डिलीवरी के एक परिवर्तनकारी मॉडल के रूप में उभरे हैं। वर्तमान में, 881 क्लिनिक—ग्रामीण क्षेत्रों में 565 और शहरी क्षेत्रों में 316—निशुल्क 107 आवश्यक दवाएं और 47 डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रदान कर रहे हैं, और लगभग 5 करोड़ से अधिक ओपीडी विज़िट दर्ज की गई हैं, जिनमें 1.55 करोड़ विशिष्ट मरीज शामिल हैं। विशेष रूप से, लाभार्थियों में 55 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच और बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

31. इस नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए, चालू वर्ष के दौरान 100 अतिरिक्त आम आदमी क्लीनिक चालू किए जा रहे हैं, और वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य भर में 143 और क्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 308 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आम आदमी क्लीनिक में अपग्रेड किया जाएगा ताकि कवरेज का विस्तार हो सके और सेवा वितरण में सुधार हो सके, जिससे भगवंत मान सरकार द्वारा पांच वर्षों में स्थापित किए जाने वाले आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,432 हो जाएगी। ये कदम पूरे राज्य में पंजाब के समुदाय-आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत करेंगे। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹351 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।

32. माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 जिला अस्पतालों और 42 उप-मंडलीय अस्पतालों में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं,

जिसमें स्वच्छता, सफाई, रोगी आराम और सेवा दक्षता पर केंद्रित व्यापक उन्नयन किया गया है। साथ ही, मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल को बढ़ाने के लिए सरकारी अस्पतालों में समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित और चालू किए जा रहे हैं, जिससे पूरे राज्य में सुरक्षित और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में और सुधार हो रहा है।

33. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राज्य सरकारी अस्पतालों के लिए नैदानिक, आपातकालीन और गंभीर देखभाल सेवाओं को बढ़ाने हेतु ₹300 करोड़ मूल्य के उन्नत चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की बड़े पैमाने पर खरीद कर रहा है। यह उन्नयन कार्य पूरा होने के करीब है और यह स्वास्थ्य सेवा क्षमता को काफी मजबूत करेगा, साथ ही पूरे पंजाब के नागरिकों को समय पर, किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करेगा।

34. साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर, सरकार श्री आनंदपुर साहिब में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर के साथ-साथ एक समर्पित मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। यह अत्याधुनिक सुविधा आपातकालीन और गंभीर देखभाल सेवाओं को मजबूत करेगी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि निवासियों के साथ-साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस पवित्र शहर के भीतर समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों, जिससे दूरस्थ केंद्रों में रेफ़र करने की आवश्यकता कम हो।

35. हमारी सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जनशक्ति को मजबूत करने के लिए पंजाब की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे बड़ा भर्ती अभियान चलाया है। 2022 से अब

तक, 934 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी जिलों में उनकी उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और विशेषज्ञ देखभाल को और बढ़ाने के लिए लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ ही, लगभग 400 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जा चुकी है, और 500 अन्य की भर्ती की प्रक्रिया जारी है, जिससे फ्रंटलाईन की स्वास्थ्य सेवा वितरण मजबूत हुआ है और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी देखभाल में सुधार हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने सैकेंडरी अस्पतालों में चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए, गैर-कार्यकारी घंटों के दौरान आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवारत विशेषज्ञों को ऑन-कॉल प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है।

36. मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु ₹6,879 करोड़ के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने और पंजाब के प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान

37. सरकार पूरे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जारी रखे हुए है। पटियाला और अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, ट्रॉमा सेंटर, छात्रावास और आवासीय सुविधाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर हैं, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2026-

27 में पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान की गई है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नवंबर 2025 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, मोहाली में पहला लिवर प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया और इस लिवर प्रत्यारोपण की लागत केवल 10 लाख रुपये थी। राज्य में तृतीयक देखभाल क्षमता को और मजबूत करने के लिए, डायग्नोस्टिक ब्लॉक के पूरा होने और 175 बिस्तरों वाले अस्पताल के विकास के साथ संस्थान का विस्तार भी किया जा रहा है।

38. माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब तेजी से उत्तरी भारत में चिकित्सा शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है, क्योंकि हम स्वास्थ्य सेवा क्रांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने होशियारपुर, कपूरथला, संगरूर, एस.बी.एस. नगर, लहरागागा, मलेरकोटला और लुधियाना में सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, जिससे राज्य की क्षमता में कुल 600 नई एमबीबीएस सीटों का इज़ाफा हुआ है। यह दृष्टिकोण वित्तीय ज़िम्मेदारी और बुनियादी ढांचे की उत्कृष्टता पर आधारित है। उदाहरण के लिए, हमने होशियारपुर मेडिकल कॉलेज की परियोजना लागत को ₹550 करोड़ से घटाकर ₹275 करोड़ कर दिया है, जिससे वैश्विक मानकों को बनाए रखते हुए लगभग ₹250 करोड़ की जनता की राशि बचाई गई है। यह रणनीतिक विस्तार सुनिश्चित करता है कि हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को अब अपनी शिक्षा के लिए यूक्रेन या चीन जैसे देशों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है; बल्कि, उन्हें यहीं पंजाब में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और एक उज्ज्वल भविष्य मिलेगा।

39. मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, सरकार ने मलेरकोटला में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 49 करोड़ रुपये की लागत से 38.50 एकड़ भूमि खरीदी है।

40. साथ ही, नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और चिन्हित जिलों में चरणबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा में क्षमता विस्तार किया जा रहा है। ये पहलें एमबीबीएस सीटों में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगी, आधुनिक शिक्षण अस्पतालों का निर्माण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि उन्नत चिकित्सा शिक्षा और विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य के सभी क्षेत्रों में सुलभ हों। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र हेतु 1220 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

कृषि और किसान कल्याण

41. अध्यक्ष महोदय, यद्यपि पंजाब देश के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा है, फिर भी यह केंद्रीय अनाज भंडार में लगभग 40 प्रतिशत गेहूं और 31 प्रतिशत चावल का योगदान देता है। देश के सबसे मजबूत कृषि विपणन नेटवर्क में से एक द्वारा समर्थित, पंजाब अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

42. इस महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखने और हमारे किसान समुदाय की लचीलापन और समृद्धि को और मजबूत करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ₹15,377 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो फसल विविधीकरण, स्थिरता,

बाजार सुधार और किसान कल्याण में लक्षित पहलकदमियों का समर्थन करेगा।

43. वर्ष 2025-26 के दौरान, कपास किसानों को समर्थन देने के लिए पीएयू द्वारा अनुशंसित बीटी कपास संकर बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी गई, जिससे 11 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से 52,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ, जिसके परिणामस्वरूप चालू सीजन में कपास के रकबे में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

44. जल-बचत खेती के तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए, डायरेक्ट सीडेड राइस (सीधी बिजाई वाले चावल) अपनाने वाले किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 35 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। श्रम की कमी को दूर करने और भूजल के संरक्षण में इसके लाभों को मान्यता देते हुए, पारंपरिक धान रोपाई के इस टिकाऊ विकल्प को और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

45. टिकाऊ फसल पैटर्न को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में, छह जिलों - पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला - में धान से खरीफ मक्का की ओर रुख करने को प्रोत्साहित करने वाली एक पायलट परियोजना लागू की गई है, जिसमें 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस उद्देश्य के लिए 15 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

46. पराली जलाने की चुनौती से निपटने के लिए, सरकार पराली प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए पंचायतों को 80 प्रतिशत और व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी

देना जारी रखे हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ऐसे उपकरणों पर सब्सिडी के लिए 402 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और वित्त वर्ष 2026-27 में 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों को मुफ़्त बिजली

47. किसान समुदाय के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, निःशुल्क और सब्सिडी वाली बिजली के प्रावधान के लिए, कृषि के लिए बिजली सब्सिडी हेतु ₹7,715 करोड़ का आवंटन किया गया है।

बागवानी

48. बागवानी परिवर्तन को गति देने के लिए, राज्य जेआईसीए (JICA) के सहयोग से अगले 10 वर्षों में कुल 1,300 करोड़ रुपये की लागत से एक केंद्रित कार्यक्रम लागू करेगा, ताकि पूरे पंजाब में जलवायु-लचीला और उच्च-मूल्य वाली बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे पंजाब में इस परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की घोषणा करते हुए अत्यधिक गर्व हो रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक फलों, सब्जियों, फूलों और औषधीय फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करना है, जो लगभग 300% की वृद्धि है। साथ ही, इसके तहत कुशल सिंचाई, एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक खेती जैसी टिकाऊ पद्धतियों को भी मजबूत किया जाएगा। यह परियोजना इस क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक पूंजी लाएगी और नवीनतम बीजों, नर्सरी, अनुसंधान, अत्याधुनिक मंडी अवसंरचना, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण अवसंरचना, साथ ही किसान प्रशिक्षण

और विस्तार सेवाओं में निवेश करेगी।

49. अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, प्रगतिशील किसानों द्वारा ड्रैगन फ्रूट की खेती में तेजी आ रही है और अधिक किसान इस उच्च मूल्य वाली फसल को अपना रहे हैं। संरचित प्रशिक्षण और मजबूत विस्तार सेवाओं के माध्यम से, पंजाब भर में किसानों को जलवायु-स्मार्ट तकनीक अपनाने और उत्पादकता में सुधार करने में सहायता प्रदान की जाएगी। बागवानी की ओर यह रणनीतिक बदलाव आय के अवसरों को बढ़ाएगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा और राज्य में दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगा।

पशुपालन

50. संबद्ध क्षेत्र राज्य भर में ग्रामीण आजीविका और स्वरोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। डेयरी विकास के क्षेत्र में, 2,000 से अधिक नई डेयरी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और डेयरी उद्यमिता कार्यक्रमों के तहत 6,500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक अतिरिक्त लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। सभी जिलों में दूध उत्पादक और उपभोक्ता जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, तथा डेयरी इकाइयों की स्थापना, मशीनीकरण और क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए मॉडल पशु शेड हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

51. डेयरी क्षेत्र में लाभप्रद प्रतिफल और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में डेयरी किसानों के लिए दूध के उचित खरीद मूल्य का समर्थन करने हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य किसानों को बाजार में होने

वाले उतार-चढ़ाव से बचाना, सहकारी खरीद प्रणालियों को मजबूत करना और राज्य भर के छोटे एवं सीमांत डेयरी उत्पादकों के लिए नियमित आय बनाए रखना है।

52. मत्स्य पालन के क्षेत्र में, निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) का विस्तार हुआ है और किसानों की क्षमता निर्माण हुआ है। सरकारी फार्मों के माध्यम से 1,500 लाख से अधिक गुणवत्तापूर्ण मछली बीज का उत्पादन किया गया है, लगभग 3,000 एकड़ नए क्षेत्र को मछली पालन के दायरे में लाया गया है, और वर्ष के दौरान मछली उत्पादन पर्याप्त स्तर पर पहुंच गया है। मछली किसानों और इच्छुक उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित किए गए हैं, साथ ही मछली पालन, झींगा पालन, बायो-फ्लॉक इकाइयों और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और बैंक-संबद्ध वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। जलीय संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नदी रैंचिंग (नदियों में मछली बीज विमोचन) पहल भी की गई हैं। ये सभी उपाय मिलकर आय विविधीकरण, रोजगार सृजन और संबद्ध कृषि क्षेत्रों में लचीलापन मजबूत कर रहे हैं।

सहकारिता

53. हमारी सरकार अपने गन्ना किसानों को मजबूत और निरंतर समर्थन देती रही है। आगामी पेराई सत्र के लिए, गन्ने का राज्य सहमति मूल्य बढ़ाकर 416 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्यों में से एक होना सुनिश्चित करता है। मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्षों के सभी लंबित गन्ना बकाये को चालू वर्ष के दौरान साफ किया जा रहा है, जिससे गन्ना किसानों को

अत्यंत आवश्यक राहत मिल रही है। हमारी सरकार गन्ना बकाये के समय पर भुगतान और चीनी क्षेत्र की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, और इस सहायता को जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹270 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

वानिकी और वन्यजीव

54. हरित आवरण और पारिस्थितिकीय लचीलापन मजबूत करने के लिए, सरकार ने राज्य के सभी जिलों में "श्री गुरु तेग बहादुर हरियावल संकल्प" अभियान शुरू किया, जिसके तहत अब तक 1.11 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। ग्रीनिंग पंजाब मिशन के तहत, शहरी और सामुदायिक हरित स्थलों का विस्तार करने के लिए नानक बगीचियाँ, पवित्तर वन और पर्यावरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में, पनकम्पा (PUNCAMPA) योजना के तहत 4,150 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का प्रस्ताव है, साथ ही स्वीकृत योजनाओं के तहत वनरोपण और वन्यजीव संरक्षण पहल की जाएगी, जिसके लिए 238 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

55. इसके अतिरिक्त, राज्य 760 करोड़ रुपये की जेआईसीए-समर्थित परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे अगले आठ वर्षों में लागू किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों के बाहर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत होगी।

ग्रामीण विकास

56. माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण संपर्क सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि कृषि, व्यापार और गांवों के संपर्क को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंजाब में 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा ग्रामीण संपर्क सड़कों का विस्तृत नेटवर्क है। वर्तमान में, 40,103 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कुल 12,597 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जिसमें नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं और संपर्क सड़कों के आधुनिकीकरण जैसे कदम शामिल हैं। निस्संदेह, यह पंजाब के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा एक ही वर्ष के भीतर शुरू किया गया सबसे बड़ा सड़क अपग्रेडेशन कार्यक्रम है।

57. चालू वर्ष के दौरान, मंडियों और ग्रामीण बाजारों तक कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 8,325 किलोमीटर को कवर करने वाले आधुनिकीकरण कार्य ₹2,393 करोड़ की अनुमानित लागत से किए जा रहे हैं। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि राज्य ने सभी उन्नत ग्रामीण सड़कों के लिए पांच वर्षीय रखरखाव घटक भी शुरू किया है, जिससे निरंतर गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, 11,901 किलोमीटर लिंक रोड को नाबार्ड सहायता से ₹2,597 करोड़ की लागत से उन्नत किया जा रहा है, और इन कार्यों को अक्तूबर, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

58. इस गति को आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शेष 19,876 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पांच वर्षीय रखरखाव सहित ₹7,606 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा करने का प्रस्ताव रखती है। सड़क बुनियादी ढांचे के अलावा, किसानों और कृषि विपणन को समर्थन देने के लिए मंडी के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।

59. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 197 करोड़ रुपये की लागत से मंडियों में 664 ढके हुए शेडों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका अधिकांश कार्य पूरा होने के करीब है। इसके अलावा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और परिचालन लागत कम करने के लिए 36 मंडियों में 24 करोड़ रुपये की लागत से सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।

60. माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे गांवों में टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण का समर्थन करने में एक सार्थक भूमिका निभाई है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव पेश किए गए हैं, हमारा मानना है कि योजना को अपनी मूल भावना और व्यापक ढांचे में जारी रहना चाहिए ताकि ग्रामीण मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और सबसे कमजोर वर्गों के लिए मजदूरी रोजगार सहायता कमजोर न पड़े।

61. चालू वर्ष में, इस योजना के तहत लगभग 1,100 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है, जिससे 223 लाख दिहाड़ियों का रोजगार सृजित हुआ है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, इस योजना के तहत कुल कार्यक्रम परिव्यय 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। राज्य

सरकार योजना को उसकी मूल भावना के साथ लागू करना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, और तदनुसार योजना के तहत राज्य के दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे कार्यों की निरंतरता, मजदूरी का समय पर भुगतान और पूरे पंजाब में ग्रामीण आजीविका को निरंतर समर्थन सुनिश्चित हो सके।

62. 2017 से मार्च 2022 तक, पंजाब में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत लगभग 39,000 घर पूरे हुए थे और हमारी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद, इस गति में निर्णायक रूप से तेजी लाई गई। कुल 76,000 परिवारों को आवास सहायता प्रदान की गई है, जिसमें 30,000 बाढ़ प्रभावित परिवार शामिल हैं। इस नवीनीकृत गति को आगे बढ़ाते हुए, सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत एक लाख और घरों को कवर करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।

रंगला पंजाब विकास योजना

63. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित और समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रंगला पंजाब विकास योजना शुरू की, जिसमें सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण और उन्नयन के लिए 585 करोड़ रुपये अर्थात प्रति विधानसभा क्षेत्र सालाना 5 करोड़ रुपये का समर्पित आवंटन प्रदान किया गया। इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रभावी कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए, हम वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस पहल का विस्तार कर रहे हैं, जिसके तहत आवंटन को 585 करोड़ रुपये

से दोगुना करके 1170 करोड़ रुपये किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास को गति दी जा सके। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के कोष से कार्यान्वयन एजेंसी तक धनराशि की रीयल टाईम ट्रैकिंग के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें कार्यों की जियो-टैग की गई निगरानी और फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण शामिल है।

शहरी विकास

64. माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसंरचना केवल एक व्यय नहीं है - यह वह नींव है जिस पर व्यवसाय बढ़ते हैं, परिवार समृद्ध होते हैं और राज्य का भविष्य सुरक्षित होता है। यह बजट केवल वित्तीय आवंटन ही नहीं, बल्कि हमारे शहरों के लिए अवसर, प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और सामाजिक समानता के केंद्र के रूप में उभरने के एक स्पष्ट दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।

65. इसी भावना के साथ, मैं हमारे शहरी स्थानीय निकायों को समर्थन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं। वित्त वर्ष 2025-26 में नगर विकास कोष (एमडीएफ) के तहत 225 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, वित्त वर्ष 2026-27 में इस अनुदान को चार गुना बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। एमडीएफ सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक नागरिक अवसंरचना जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिताएँ, सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अवसंरचना के निर्माण और

उन्नयन के लिए उपलब्ध होगा। इस फ़ंड में से 20 प्रतिशत का उपयोग जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए किया जा सकता है। यह न केवल संपत्ति सृजन सुनिश्चित होगा बल्कि सेवाओं का निरंतर वितरण भी सुनिश्चित होगा।

66. पंजाब सरकार, विश्व बैंक और एआईआईबी के सहयोग से चल रही पंजाब नगर सेवा सुधार परियोजना के तहत, जो एक नहर-आधारित सतही जल आपूर्ति पहल है, लुधियाना और अमृतसर में दीर्घकालिक शहरी जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य चल रहे हैं। 2028 तक पूरा होने वाली इस परियोजना में बड़ी क्षमता वाले जल उपचार संयंत्र, उच्च स्तरीय सेवा जलाशय और ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण शामिल है। इस परिवर्तनकारी शहरी जल अवसंरचना कार्यक्रम को जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

67. अमृत 2.0 के तहत, परियोजनाओं को दो चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें नए जल उपचार संयंत्रों का निर्माण, जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना और उनका पुनर्वास, नए घरेलू कनेक्शन, सीवरेज कार्य, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, पार्कों और हरित स्थानों का विकास, और जल निकायों का कायाकल्प शामिल है। कुल 214 परियोजनाओं को, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 3,504 करोड़ रुपये है, मंजूरी दी जा चुकी है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, 149 शहरी स्थानीय निकायों में शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार में तेजी लाने के लिए 665 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान व्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

68. इसके अतिरिक्त, योजना, निगरानी और सेवा वितरण में सुधार के लिए जीआईएस आधारित शहरी मानचित्रण में राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। 163 शहरी स्थानीय निकायों में वार्ड और नगर पालिका की सीमाओं को डिजिटल कर दिया गया है, और केंद्रीकृत डेटा एकीकरण एवं रियल-टाइम निगरानी को सक्षम करने के लिए 'वन मैप पंजाब' जीआईएस पोर्टल को कार्यान्वित कर दिया गया है।

69. योजनाबद्ध शहरीकरण को और मजबूत करने और नागरिक अवसंरचना में सुधार के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र के लिए ₹7,257 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव है।

उद्योग और वाणिज्य

70. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के सुधार-उन्मुख दृष्टिकोण ने पंजाब की आर्थिक क्षमता में विश्वास बहाल करना शुरू कर दिया है। मार्च 2022 से अब तक, राज्य को ₹1,45,371 करोड़ के 8,049 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा, वर्ष 2025 में ₹55,000 करोड़ का निवेश प्राप्त होने से यह गति और तेज़ हो रही है - जो पंजाब के इतिहास में किसी एक वर्ष में सबसे अधिक है। यह नवीकृत निवेशक विश्वास राज्य में बढ़ते विदेशी निवेश में भी परिलक्षित होता है, जो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025 में 2022 की तुलना में दोगुना हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य समग्र एफडीआई प्रवाह में पिछली 15वीं रैंक से अब 11वें स्थान पर पहुंच गया है।

71. माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च 2022 से अब तक, विभिन्न नीति ढाँचों के तहत लगभग 1,198 औद्योगिक इकाइयों को ₹14,734 करोड़ की राजकोषीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा सब्सिडी वाली बिजली दरों पर ₹9,275 करोड़ का वहन किया गया है।

72. सरकार ने लंबे समय से लंबित औद्योगिक बकाया के निपटान और औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार में सहायता के लिए 'एकमुश्त निपटान' (OTS) योजनाएं शुरू की हैं। इस पहल से लगभग 3,100 औद्योगिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा, औद्योगिक प्लॉटों की बढ़ी हुई भूमि की कीमत और मूल लागत से संबंधित बकाया राशियों के निपटान के लिए एक अलग 'एकमुश्त निपटान' नीति अलग से पेश की गई है।

73. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले चार वर्षों में रखी गई मजबूत नींव पर निर्माण करते हुए और उभरते औद्योगिक अवसरों के प्रत्युत्तर में, हमारी सरकार ने औद्योगिक नीति 2026 मंज़ूरी दी है ताकि कारोबार करने में सुगमता को और मजबूत किया जा सके, क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों का विस्तार किया जा सके और निवेश-संचालित विकास को गति दी जा सके। यह नीति कोई साधारण संशोधन नहीं है, बल्कि पंजाब उद्योग क्रांति पहल के माध्यम से किए गए एक व्यापक भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है, जिसके तहत 24 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया और "राइज़िंग पंजाब - सुझाव से समाधान तक" के तहत राज्यव्यापी परामर्श आयोजित किए गए। नीति निर्माण को सीधे उद्योग हितधारकों के हाथों में रखकर, हमने सुनिश्चित किया है कि नई औद्योगिक नीति 2026 वास्तविक

व्यावसायिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करे, परिचालन चुनौतियों का समाधान करे और पंजाब को रोजगार-उन्मुख और टिकाऊ औद्योगिक विस्तार के अगले चरण के लिए तैयार करे।

74. इस पालसी इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करते हुए, हमारे औद्योगिक ढांचे में पारदर्शिता और निवेशकों के विश्वास को और गहरा करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है। 'फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल' मान्यता प्राप्त स्वीकृति तंत्र के साथ समयबद्ध, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सुनिश्चित करता है, जबकि 'पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट' में किए गए संशोधन पात्र उद्यमों को स्व-घोषणा आधारित सैद्धांतिक अनुमोदन के माध्यम से परिचालन शुरू करने की अनुमति देते हैं। औद्योगिक भूमि प्रबंधन में सुधार - जिसमें एकमुश्त समाधान प्रावधान, लचीली प्लॉट उपयोग नीतियां और सुव्यवस्थित रूपांतरण तंत्र शामिल हैं - ने लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर किया है। साथ ही, विवाद समाधान प्रणालियों, क्लस्टर विकास पहलों, लाजिस्टिक संवर्धन और डिजिटल सुविधा प्लेटफार्मों के माध्यम से एमएसएमई को मजबूत समर्थन यह सुनिश्चित कर रहा है कि औद्योगिक विकास व्यापक-आधारित, रोजगार-उन्मुख और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बना रहे।

75. पंजाब की औद्योगिक गति को सुदृढ़ करने के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए 2,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए निरंतर सहायता और विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु 500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि शामिल है।

रोजगार सृजन और प्रशिक्षण

76. रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। वर्ष 2022 से अब तक, 63,943 उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती की गई है।

77. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्य भर में आयोजित 1,356 से अधिक प्लेसमेंट कैंप और जॉब फेयर के माध्यम से 70,000 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली। इसके अलावा, 261 स्वरोजगार शिविरों के माध्यम से 15,000 से अधिक उम्मीदवारों को उद्यमशीलता उपक्रमों के लिए ऋण सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया, जबकि 2.95 लाख से अधिक उम्मीदवारों को व्यापक कैरियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

78. पंजाब खुद को रक्षा और रणनीतिक क्षेत्र के कौशल के लिए एक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहा है। जनवरी 2026 में एक रक्षा कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ताकि प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख औद्योगिक निकायों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियाँ हुईं। पंजाब कौशल विकास मिशन के तहत, सेवा और विनिर्माण व्यवसायों में हजारों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और प्लेसमेंट जारी है।

79. सी-पीवाईटीई केंद्र युवाओं को सशस्त्र बलों के लिए तैयार करना जारी रखे हुए हैं, वहीं सशस्त्र बल प्रारंभिक संस्थानों ने सफल अधिकारी कमीशन दर्ज किए हैं, जिनमें

महिला कैडेटों की बढ़ती भागीदारी भी शामिल है। होशियारपुर के बजवाड़ा में नव स्थापित सरदार बहादुर अमीन चंद सोनी सशस्त्र बल प्रारंभिक संस्थान, जो लगभग पूरा हो चुका है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश परीक्षाओं और एसएसबी तैयारी के लिए समर्पित विंग के साथ प्रशिक्षण शुरू कर देगा, जिससे रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए पंजाब के युवाओं के लिए संरचित मार्गों का और विस्तार होगा। विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 287 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है ।

युद्ध नशियां दे विरुद्ध

80. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पिछले बजट में आश्वासन दिया गया था, 'युद्ध नशियाँ दे विरुद्ध' को एक अस्थायी अभियान के रूप में नहीं, बल्कि नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक निरंतर जारी रहने वाले अभियान के रूप में चलाया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 52,331 तस्करों के विरुद्ध 36,686 मामले दर्ज किए गए, और खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशनों के माध्यम से 33,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। नशीली दवाओं की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने के लिए वित्तीय जाँच को और मजबूत किया गया है। इसके साथ ही, लगभग 12,000 ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक सदस्य और हजारों 'पिंड दे पहरेदार' स्वयंसेवक शामिल हैं, जिन्हें सामुदायिक निगरानी के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संगठित किया गया है। मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दो महीनों में अकेले ग्राम रक्षा समितियों की जानकारी के आधार पर 350 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 510

व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

81. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स जनता के विश्वास को बहाल करने में निरंतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके गठन के बाद से अब तक 2,762 गैंगस्टरों और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, 34 को मार गिराया गया है, 1,062 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और 2,203 हथियार बरामद किए गए हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में, हम उन्नत साइबर और फोरेंसिक क्षमताओं, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के मजबूत अभियानों, डिजिटल निगरानी प्रणालियों और आपराधिक नेटवर्कों के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करके इस संस्थागत दृष्टिकोण को और गहरा करेंगे। इस प्रकार, 'युद्ध नशियाँ दे विरुद्ध' प्रवर्तन कार्रवाई से विकसित होकर एक दीर्घकालिक शासन ढांचे का रूप ले रहा है—जो कार्रवाई में दृढ़, खुफिया जानकारी में सटीक और पंजाब के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के अपने संकल्प में अटूट है।

82. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में घोषणा के अनुसार, राज्य ने नशा और सामाजिक-आर्थिक जनगणना पहल पर निर्णायक रूप से आगे बढ़त हासिल की है। चालू वर्ष के दौरान, आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सटीकता, पारदर्शिता और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का विकास और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण शामिल है। इस तैयारी के आधार पर, जनगणना अप्रैल-2026 से शुरू की जाएगी, जिससे सरकार विश्वसनीय, साक्ष्य-आधारित आंकड़े तैयार कर सकेगी, जो लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेंगे और नशे के दुरुपयोग के

खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 में इस महत्वपूर्ण पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

खेडदा पंजाब, बदलदा पंजाब

83. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष ऐतिहासिक पहल "खेड-दा पंजाब, बदलदा पंजाब" के तहत, हमने घोषणा की थी कि नशे के खिलाफ लड़ाई न केवल प्रवर्तन के माध्यम से लड़ी जाएगी, बल्कि हमारे युवाओं को रचनात्मक, अनुशासित और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल करके लड़ी जाएगी। हमने गांवों में मॉडल खेल के मैदान और जिम बनाने और जमीनी स्तर पर पंजाब की खेल संस्कृति को बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी जिलों में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं - 3,000 से अधिक मॉडल गांव के खेल मैदान, जिनमें लेजर-लेवल वाले मैदान, जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पुरुषों और महिलाओं के शौचालय और हाई-मास्ट लाइटें शामिल हैं, वर्तमान में 1,100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन हैं और जून 2026 तक पूरे हो जाएंगे। इसी तरह, 1000 ग्रामीण इनडोर जिम वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और अप्रैल 2026 तक पूरे हो जाएंगे। पंजाब के इतिहास में किसी भी सरकार द्वारा खेलों में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इन प्रयासों ने युवाओं में नया उत्साह पैदा किया है और गांव के खेल के मैदानों को जीवंत सामुदायिक स्थलों में बदलना शुरू कर दिया है।

84. माननीय अध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई मजबूत गति को आगे बढ़ाते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष हमारे खेल बुनियादी ढांचे और एथलीट सहायता ढांचे में एक निर्णायक विस्तार का प्रतीक है। हमारी सरकार ने पूरे राज्य में 6,000 अतिरिक्त गांव के खेल मैदान और 5,000 अतिरिक्त इनडोर जिम बनाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक पूर्ण हो चुके गांव के खेल मैदान में, हमारी सरकार स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा।

85. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस व्यापक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप के पैमाने को दर्शाते हुए, मुझे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,791 करोड़ के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह आवंटन केवल व्यय में रिकार्ड वृद्धि मात्र नहीं है, बल्कि पंजाब भर में खेल विकास को संस्थागत बनाने की दिशा में एक स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता है। इस बढ़े हुए निवेश के साथ, हम जमीनी स्तर की भागीदारी से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता तक एक व्यवस्थित मार्ग का निर्माण कर रहे हैं।

पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले

86. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की 350वीं वर्षगांठ थी। गुरु साहिब जी के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए, हमारी

सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में गहरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एक विशेष तीन दिवसीय स्मारक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा, नवंबर 2025 में श्री आनंदपुर साहिब में पंजाब विधान सभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें गुरु साहिब जी को श्रद्धांजलि दी गई और पंजाब के गौरवशाली इतिहास और मूल्यों से जुड़े रहने के हमारे सामूहिक संकल्प को दोहराया गया।

87. माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब का आध्यात्मिक और सामाजिक ताना-बाना महान संतों और सुधारकों की अनन्त शिक्षाओं द्वारा आकार दिया गया है। इसी भावना के साथ, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੈ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ।

ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ।

88. श्री गुरु रविदास जी का समानता, एक ईश्वर के प्रति भक्ति और जातिगत भेदभाव की अस्वीकृति का संदेश लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा है, और बेगमपुरा - दुख और अन्याय से मुक्त समाज - का उनका सपना आज भी गहराई से प्रासंगिक है। मुख्य समारोह श्री गुरु रविदास जी स्मारक, गांव खुरालगढ़, जिला होशियारपुर में प्रस्तावित हैं, जिन्हें उनका तप-अस्थान माना जाता है, जहाँ से उन्होंने सामाजिक सद्भाव और मानवीय गरिमा का संदेश फैलाया था। साथ ही, सरकार पूरे वर्ष पंजाब के सभी हिस्सों में स्मरणोत्सव गतिविधियाँ आयोजित करेगी, जो न केवल उनकी आध्यात्मिक विरासत का सम्मान

करेंगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी प्रगति के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दोहराएँगी। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹100 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है।

89. हमारी सरकार पंजाब के लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आध्यात्मिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित है, जिनके लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष मुख मंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है ताकि दो सर्किटों में बंटे - श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त और पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त तीर्थयात्रा प्रदान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी और सेवा केंद्र

90. पंजाब ने केंद्रित डिजिटल सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है, जिससे नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। राज्य प्रकरण लंबितता डैशबोर्ड ने विभागों में वास्तविक समय पर निगरानी शुरू की, जिससे एक वर्ष के भीतर लंबितता 14% से घटकर 0.33% हो गई और आवेदनों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित किया गया। आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र सहित 13 प्रमुख सेवाओं के लिए भौतिक फॉर्म समाप्त कर दिए गए, जिससे पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन संभव हो गए और कार्यालयों के चक्कर कम हो गए।

91. माननीय अध्यक्ष महोदय, "भगवंत मान सरकार तुहाडे द्वार" पहल नागरिक-केंद्रित शासन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, जो सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचा रही है। 2025 में इसका 43 सेवाओं से 412 सेवाओं तक विस्तार कर दिए जाने के साथ, अब पूरे पंजाब के निवासी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए बिना विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय, लागत और असुविधा में उल्लेखनीय कमी आई है। इस सुधार को पूरक बनाते हुए, सभी 56 परिवहन-संबंधी सेवाओं को सेवा केंद्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे आरटीए/डीटीओ कार्यालयों में पारंपरिक सार्वजनिक काउंटरों को हटा दिया गया है और पूरे राज्य में एक समान, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण सुनिश्चित किया गया है। ये सभी उपाय मिलकर सार्वजनिक सेवा वितरण में पहुंच, दक्षता और गरिमा के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

राजस्व एवं पुनर्वास

92. माननीय अध्यक्ष महोदय, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादती दिवस के उपलक्ष्य में, सरकार श्री आनंदपुर साहिब में एक नया प्रशासनिक परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है, जिसे विरासत शैली की वास्तुकला में डिजाइन किया जाएगा जो पवित्र शहर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह परिसर प्रमुख सरकारी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाएगा, प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करेगा, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करेगा और नागरिकों के लिए अधिक सुविधा सुनिश्चित करेगा, साथ ही श्री आनंदपुर साहिब के पारंपरिक स्वरूप और पवित्र पहचान को

संरक्षित और बढ़ावा देगा।

93. हमारी सरकार ने राजस्व विभाग ने भूमि और संपत्ति सेवाओं को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने "ईज़ी जमाबंदी" पहल शुरू की है, जिससे निवासी एक ऑनलाइन पोर्टल या यहां तक कि व्हाट्सएप के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं, इंतकाल के लिए आवेदन कर सकते हैं, रपट प्रविष्टियों का अनुरोध कर सकते हैं और फर्द बदर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सेवा सहायकों द्वारा घर-घर जाकर सहायता प्रदान की जाती है। इसके पूरक के रूप में, "ईज़ी रजिस्ट्री" परियोजना ने दस्तावेज़ प्रारूपों को सरल बनाकर, पूरे जिले में पंजीकरण का विकल्प सक्षम करके और नागरिकों को वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करके संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और प्रक्रियात्मक जटिलता कम हुई है। 'ईज़ी रजिस्ट्री' पहल के तहत पंजाब में कुल 6.17 लाख रजिस्ट्रियां सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि उप-पंजीयक कार्यालय में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए इस बड़े सुधार प्रयास को व्यापक स्वीकार्यता मिली है।

94. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ से हमारी सहनशक्ति की परीक्षा हुई थी, और मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारा जवाब त्वरित और व्यवस्थित था। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, आपदा राहत और शमन के लिए 1,010 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस आवंटन ने फसल क्षति, मकानों के नुकसान और पशुधन की हानि के लिए प्रत्यक्ष मुआवजा प्रदान किया है, साथ ही राज्य शमन कोष के तहत महत्वपूर्ण निवेश भी

किए हैं। हमारी प्रतिक्रिया को जो चीज़ अलग बनाती है, वह है भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल बाढ़ राहत प्रणाली की शुरुआत। मैनुअल प्रक्रियाओं से हटकर तीव्र जियो-टैग किए गए सर्वेक्षणों और वास्तविक समय की निगरानी की प्रणाली अपनाकर, हमने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और समय लेने वाली प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्लेटफ़ार्म सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रुपया सीधे ऑनलाइन हस्तांतरण के माध्यम से इच्छित लाभार्थी तक पहुंचे, जिससे हजारों बाढ़ प्रभावित परिवारों को वह समय पर सहायता मिल सके जिसके वे हकदार हैं - बिना किसी देरी के, बिना किसी बिचौलिए के और पूर्ण पारदर्शिता के साथ। हमारे लगभग सभी लाभार्थियों को बाढ़ के कुछ महीनों के भीतर ही उनका धन प्राप्त हो गया, जबकि अतीत में इसमें 06 महीने से लेकर एक वर्ष तक का समय लग जाता था।

95. प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए नई उप-मंडलियों (सब-डिवीजनों) और उप-तहसीलों (सब-तहसीलों) का सृजन और उन्नयन किया गया है। विभिन्न जिलों में नए एसडीएम और तहसील कॉम्प्लेक्स को चालू करके शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो और जिस तक पहुंचना आसान हो।

गृह मामले, न्याय और जेल

96. माननीय अध्यक्ष महोदय, आंतरिक सुरक्षा वह नींव है जिस पर हर सुधार टिका होता है। जहाँ कानून व्यवस्था अनिश्चित हो, वहाँ विकास जड़ें नहीं जमा सकता। पिछले चार वर्षों में, इस सरकार ने प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग से हटकर एक संरचित, खुफिया

जानकारी-आधारित सुरक्षा ढांचे की ओर कदम बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के बजाय संगठित आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, मैं गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित करता हूं, जो संस्थागत क्षमता, तकनीकी क्षमता और परिचालन तत्परता को मजबूत करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

97. पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिलों में 636 सामरिक स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाकर रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित करना, प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,719 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों में नियंत्रण कक्ष चालू हो गए हैं, जिससे चौबीसों घंटे निगरानी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को काफी मजबूत किया है।

98. आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली - डायल 112 - ने एक महत्वपूर्ण नागरिक सहायता मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया है, जिसने शुरुआत से अब तक 2.62 करोड़ से अधिक कॉलों को एटेंड किया है। सड़क सुरक्षा बल ने निर्धारित राजमार्ग खंडों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को 6-7 मिनट तक कम करके सार्वजनिक सुरक्षा को और बढ़ाया है, जिससे पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में ठोस सुधार हुए हैं। चालू वर्ष के दौरान, डायल-112 के तहत सहायता प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 508 चार-पहिया वाहन खरीदे जा रहे हैं।

99. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार उन्नत सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के माध्यम से जेल प्रशासन को भी मजबूत कर रही है। प्रमुख और संवेदनशील जेलों में अनधिकृत संचार पर रोक लगाने के लिए उन्नत वी-कवच 2.0 जैमर प्रणाली स्थापित की जा रही है, और निगरानी तथा आंतरिक सुरक्षा में सुधार के लिए एआई-आधारित सीसीटीवी निगरानी का विस्तार किया जा रहा है।

100. वित्त वर्ष 2026-27 में विभिन्न पहलकदमियों को शुरू करने के लिए ₹535 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है, जिसमें सुरक्षा आधुनिकीकरण, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और क्षमता वृद्धि शामिल है।

आधारभूत संरचना

सड़कें एवं पुल

101. हमारी सरकार न केवल राज्य भर में सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, बल्कि मौजूदा परिसंपत्तियों के व्यवस्थित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव हेतु आवंटन को वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) की तुलना में दोगुना करके ₹5,440 करोड़ कर दिया गया है। यह टिकाऊ और सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे पर हमारी सरकार की निरंतर प्राथमिकता को पुनः पुष्टि करती है।

102. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य भर में 2,570 किलोमीटर लंबी प्लान सड़कों के उन्नयन और संपर्कता सुधार के लिए 1500 करोड़ रुपये शुरूआती का परिव्यय प्रस्तावित

है, जिससे जिले के भीतर और अंतर-जिला सड़क नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, 31 कार्य अधीन पुलों के पूरा होने और नए पुल कार्यों को शुरू करने के लिए 130 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं।

103. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के ₹290 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 में, इस योजना के तहत ₹400 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ 400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। साथ ही, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष (CRIF) के तहत 100 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन और 06 आरयूबी/आरओबी (रेलवे अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज) के निर्माण के लिए ₹300 करोड़ की राशि प्रस्तावित है, जिससे राज्य भर में सड़क संपर्क और सुरक्षा मजबूत होगी।

जल आपूर्ति और स्वच्छता

104. स्वच्छ पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, 1,230 गुणवत्ता-प्रभावित और जल-तनावग्रस्त गांवों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 11 प्रमुख सतही जल परियोजनाओं को पूरा करने और चालू करने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। 125 बस्तियों में पेयजल राहत कार्य भी किए जाएंगे, साथ ही गंभीर पेयजल गुणवत्ता चुनौतियों से निपटने के लिए 88 यूरेनियम-प्रभावित क्षेत्रों में नई परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इन

पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं विभिन्न जल और स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत 1,487 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ-साथ नल जल मित्र पहल शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसका उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर जल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करना है।

जल संसाधन

105. माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे पुनर्जीवित नहर नेटवर्क के बहते पानी में साफ़ झलकती है। मात्र तीन वर्षों में, हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है: अपनी नहरी सिंचाई क्षमता को दोगुना कर दिया है। नहरों और जलमार्गों (वाटरकोर्स) के बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार के माध्यम से, हम वर्ष 2022 में 2.23 मिलियन एकड़ से बढ़कर अप्रैल 2026 तक 5.3 मिलियन एकड़ तक अपनी पहुंच का विस्तार कर लेंगे।

106. यह केवल क्षेत्र का विस्तार नहीं है, बल्कि संसाधनों का अनुकूलन है। व्यवस्थित सफाई, लाइनिंग (अस्तर) और आधुनिकीकरण से प्रेरित होकर, हमारे सतही जल के उपयोग में उछाल आया है जो बढ़कर 6.6 मिलियन एकड़-फीट (MAF) हो गया है - यह 13 प्रतिशत की छलांग है जो हमारे कृषि भविष्य को सुरक्षित करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने दशकों की उपेक्षा को सुधारा है। आज, नहर का पानी पहली बार 1,365 स्थानों पर पहुंचा है, जिससे उन गांवों में जान आ गई है जो 20 से 50 वर्षों से सूखे पड़े थे। कंक्रीट लाइनिंग, नई पाइपलाइनों और मरम्मत किए गए माइनरों के माध्यम से, हमने सुनिश्चित

किया है कि पानी अब कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार नहीं रह गया है, बल्कि यह एक अधिकार है जो अंतिम छोर (टेल-एंड) तक पहुंचाया जा रहा है।

107. साल 2025 में आई बाढ़ के बाद, राज्य की सभी प्रमुख नदियों का व्यापक मूल्यांकन किया गया और इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर, 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की 371 बाढ़ सुरक्षा एवं नियंत्रण परियोजनाओं की पहचान की गई। इनमें से, 489 करोड़ रुपये लागत के 142 कार्यों को 31 मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जबकि शेष कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में किए जाएंगे। इन बाढ़ों से सबक लेते हुए, नदियों की प्राकृतिक जल-वहन क्षमता को बहाल करने और पंजाब में दीर्घकालिक बाढ़ सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संरचित, पारदर्शी और पर्यावरण-अनुकूल नदी की डीसिल्टिंग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

108. सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 65 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ सुरक्षा और नालों की सफाई के कार्य किए हैं। विभिन्न जिलों में लगभग 3,000 किलोमीटर नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे जल निकासी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि इन कार्यों को विभागीय मशीनरी के माध्यम से करवाकर लगभग 60 प्रतिशत की बचत की गई है, जिससे कार्यकुशलता और जनता के धन का सदुपयोग सुनिश्चित हुआ है।

109. सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नहरों के जीर्णोद्धार और लाइनिंग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इन कार्यों को कई स्थलों पर पहले ही क्रियान्वित किया

जा रहा है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त 04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बेहतर सिंचाई सुविधा के दायरे में लाना है। अब तक इन कार्यों को करने पर 1,153 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

110. इसके अलावा, सरकार ने फिरोजपुर फीडर को मजबूत करने का कार्य किया है, जो 1952-53 में निर्मित एक प्रमुख नहर प्रणाली है जो फिरोजपुर, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और फरीदकोट जिलों को सेवा प्रदान करती है और 1,000 से अधिक गांवों को लाभान्वित करती है। पानी की उपलब्धता में सुधार के लिए, इस परियोजना का उद्देश्य फीडर की वहन क्षमता को 2,600 क्यूसेक बढ़ाकर 13,845 क्यूसेक तक करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 195 करोड़ रुपये की लागत से 17 किमी नहर लाईनिंग का कार्य किया गया है, जिससे अबोहर और फाजिल्का जैसे अंतिम छोर क्षेत्रों में बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी और राज्य को नहर के पानी के अपने पूरे हिस्से का उपयोग करने में मदद मिलेगी।

111. इसके अलावा, काठगढ़ लिफ्ट स्कीम चरण-II लागू की जा रही है, जिससे शहीद भगत सिंह नगर जिले के अर्ध-पहाड़ी और जल-संकटग्रस्त क्षेत्र में पहली बार नहर का पानी पहुंचाया जा सकेगा। 107 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना के तहत बिस्त दोआब नहर से पानी उठाकर 24 गांवों में फैले लगभग 5,500 एकड़ सिंचित क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पहल भूजल पर निर्भरता कम करेगी और इस से ऊर्जा बचत होने की भी उम्मीद है।

112. सिंचाई में समानता सुनिश्चित करने और मलेरकोटला क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए, सरकार ने 288 करोड़ रुपये की लागत से महोरना वितरिका के रिमाडलिंग और मलेरकोटला माइनर के निर्माण का कार्य किया है। यह परियोजना पहली बार 55 गांवों को नहर का पानी उपलब्ध कराएगी, जो लगभग 44,000 एकड़ के कमांड क्षेत्र को कवर करेगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस उद्देश्य के लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

113. वित्तीय वर्ष 2026-27 में, सरकार ने सतही जल के उपयोग को बढ़ाने और भूजल संरक्षण के दोहरे उद्देश्य से नहरी सिंचाई के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (कमांड एरिया) का और विस्तार करने की योजना बनाई है। सिंचाई क्षेत्र को लगभग पाँच लाख हेक्टेयर तक बहाल करने की उम्मीद के साथ, पाइपलाइनों और ईंट-निर्मित जलमार्गों के निर्माण के माध्यम से अंतिम-छोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र हेतु 2,971 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।

114. मैं पंजाब के लोगों के साथ यह वादा करते हुए गर्व महसूस करता हूँ कि इस कार्य के परिणामस्वरूप, साल के अंत तक नहर सिंचाई के तहत कुल क्षेत्रफल 7 मिलियन एकड़ के करीब होगा; जो कि निर्धारित नहर सिंचित क्षेत्र का लगभग 90% है।

बिजली

115. बिजली क्षेत्र में, मुख्यमंत्री माननीय सरदार भगवंत मान जी के गतिशील नेतृत्व में, पंजाब व्यापक और संरचनात्मक सुधार कर रहा है और साथ ही अपने लोगों से किए गए

हर वादे को पक्के तौर पर निभा रहा है। हमने सुनिश्चित किया है कि सूबे लगभग 90% घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलती रहे, जो हमारी घरेलू बिजली सब्सिडी के सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाता है — एक ऐसी वचनबद्धता जो जारी रहेगी। खेती के लिए किसानों और उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग को, नीति के अनुसार, हमारा समर्थन बिना किसी कमी के जारी रहेगा। परंतु, जहाँ हमारी कल्याण संबंधी वचनबद्धताएँ दृढ़ हैं, वहीं कुशलता के लिए हमारा इरादा भी मजबूत है। केंद्रित ऊर्जा सुधारों, मजबूत बिजली प्रबंधन, और प्रणालीगत कुशलता उपायों के माध्यम से, हमने प्रभावी ढंग से सूबे पर सब्सिडी का बोझ 25% तक कम करने में सफल रहेंगे। इस साल, पी.एस.पी.सी.एल. ने अपने लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन घाटे को और कम करने और कार्य-कुशलता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महान सदन में मैं गर्व से कहता हूँ कि भले ही हमारी बिजली सब्सिडी नीति और लाभार्थियों का कवरेज बिल्कुल यथावत है, फिर भी हम सुधार-आधारित कुशलता लाभों के माध्यम से लगभग ₹5,000 करोड़ की बचत करने के करीब हैं। यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि सुचारू प्रशासन और अनुशासित सुधार एक साथ लोक कल्याण करने के साथ-साथ राज्य के खजाने को भी मजबूत बना सकते हैं।

116. अध्यक्ष महोदय, हमने 'मिशन रोशन पंजाब' की भी शुरुआत की है – जिसके माध्यम से हम पंजाब के बिजली वितरण नेटवर्क को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और विस्तार करने के लिए ₹5,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं — यह राज्य के इतिहास में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) से जुड़ी सबसे बड़ी पहलों में से एक है। हमारा मिशन स्पष्ट है: हर घर, खेत और कारखाने तक निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति - 24 घंटे, 365 दिन। नियोजित

कार्यों में शामिल हैं: नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और तकनीकी नुकसान कम करने के लिए 70 नए सबस्टेशनों का निर्माण; विश्वसनीयता में सुधार के लिए 200 मौजूदा सबस्टेशनों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण; 25,000 किलोमीटर लाइनें बिछाई या अपग्रेड की जा रही हैं - जिससे सबसे दूरस्थ बस्तियों तक भी पहुंच सुनिश्चित होगी; ओवरलोडिंग और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए 8,000 नए वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) स्थापित या अपग्रेड किए जा रहे हैं; और सामग्रियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम खरीद की जा रही है ताकि जमीनी स्तर पर कार्य निर्बाध और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके।

नागरिक उड्डयन

117. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आदमपुर हवाई अड्डा अब लगभग ₹140 करोड़ की लागत से विकसित एक आधुनिक टर्मिनल सुविधा के साथ चालू हो गया है। यह हवाई अड्डा, जो पहले एक छोटे पोर्टा-केबिन सुविधा के साथ संचालित होता था, अब बेहतर यात्री प्रबंधन क्षमता और उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस है। आदमपुर से हिंडन (गाजियाबाद), मुंबई और अन्य गंतव्यों के लिए उड़ान संचालन पहले ही शुरू हो चुका है, जिससे दोआबा क्षेत्र के लिए हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और आर्थिक गतिविधियों एवं क्षेत्रीय विकास के नए मार्ग खुले हैं।

118. इसके अतिरिक्त, लुधियाना के पास लंबे समय से प्रतीक्षित हलवारा हवाई अड्डा अब संचालित थो चुका है, जो पंजाब के विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह नवनिर्मित सिविल टर्मिनल लुधियाना और व्यापक मालवा क्षेत्र

की सेवा करेगा, जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक बेल्टों में से एक है। उड़ान संचालन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद के साथ, यह हवाई अड्डा क्षेत्रीय संपर्क को काफी बढ़ावा देगा, उद्योग और व्यवसायों के लिए यात्रा की सुगमता सुनिश्चित करेगा और पंजाब के एक प्रमुख आर्थिक एवं औद्योगिक केंद्र के रूप में लुधियाना की स्थिति को और मजबूत करेगा।

खनन

119. अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा घोषित राज्य खनन तत्परता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। पंजाब की शीर्ष रैंकिंग इस क्षेत्र में पारदर्शी शासन, वैज्ञानिक खनन और निवेश सुविधा के उद्देश्य से किए गए निरंतर सुधारों की सफलता को दर्शाती है।

120. सरकार ने प्रमुख विधायी और नीतिगत सुधारों के साथ-साथ उनके अधिसूचित नियमों के माध्यम से खनन क्षेत्र के नियामक ढांचे को और मजबूत किया है, जिससे क्रशर इकाइयों और खनिज व्यापारियों के पंजीकरण और संचालन के लिए एक स्पष्ट और मजबूत रूपरेखा स्थापित हुई है, और निष्कर्षण से उपभोग तक लघु खनिज मूल्य श्रृंखला की संपूर्ण डिजिटल निगरानी संभव हुई है। पंजाब लघु खनिज नियमों में संशोधन ने साइटों की एक नई श्रेणी भी बनाई है – क्रेशर खनन साइटें और भूस्वामी खनन साइटें, जो पारदर्शी और समयबद्ध अनुबंधों को सक्षम बना रही हैं, विशेष रूप से उन भूस्वामियों के लिए जो अपनी भूमि पर खुद कार्य करना चाहते हैं।

121. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन निरंतर प्रयासों के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक पोस्ट स्थापित करने, बेहतर प्रवर्तन और आधुनिक नीलामी प्रक्रिया जैसे

नीतिगत सुधारों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष खनन से हमारे राजस्व में एक ही वर्ष में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है, जो ₹260 करोड़ से बढ़कर ₹500 करोड़ से अधिक हो गया है!

परिवहन

122. महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के अलावा, हमारी सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर। वर्तमान में 2,267 बसें परिचालन में हैं और सरकार खरीद और पट्टे के सुमेल के माध्यम से मौजूदा बेड़े में 1,279 नई बसें जोड़ेगी। कुछ नई बसें पहले से ही चालू हैं और शेष नवंबर 2026 तक चालू हो जाएंगी। यह पंजाब के इतिहास में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक विस्तार होगा। कुल मिलाकर, पीआरटीसी को 670 बसों को शामिल करके मजबूत किया जाएगा, जबकि कुल विस्तार से शेष 609 बसें पंजाब रोडवेज (PUNBUS) का हिस्सा बन जाएंगी। इन बसों को नवीनतम सुरक्षा और पहुंच मानकों से भी सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें कम गतिशीलता वाले यात्रियों और व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर प्रवेश प्रणाली, मजबूत अग्नि पहचान प्रणाली, तथा रात्रि लैंप, एलईडी लाइटिंग, जीपीएस और सीसीटीवी जैसी सुरक्षा विशेषताएं शामिल होंगी - जो हमारे नागरिकों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा सुनिश्चित करेंगी।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति

123. अध्यक्ष महोदय, आप सरकार ने राज्य भर के कमजोर परिवारों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए "मेरी रसोई" योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत, एनएफएसए/स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत कवर किए गए लगभग 40 लाख परिवारों को उनके मौजूदा खाद्यान्न अधिकार के अतिरिक्त, आवश्यक वस्तुओं जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलो चना दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 200 ग्राम हल्दी और 1 किलो नमक युक्त तिमाही राशन किट निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यह कार्यक्रम परिवारों के खर्च को कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन करने के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 900 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

124. इसके अलावा, लोगों की एक लंबे समय से मांग रही है कि नए राशन कार्डों के लिए पंजीकरण खोला जाए ताकि इस राज्य में, जो पूरे देश का पेट भरता है, पंजाब का कोई भी गरीब परिवार कभी भी अपनी थाली में पर्याप्त भोजन की चिंता न करे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी के निर्देशानुसार, हम आगामी वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा के द्वार खोलेंगे, उनका स्वागत करेंगे जो लंबे समय से अपने अधिकारपूर्ण समावेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समानता की विजय है, यह सुनिश्चित करना कि हमारे राज्य की प्रगति के लाभ हमारे बीच के ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुँचें।

125. पंजाब के हर परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ, हमारी सरकार अपने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने राज्य में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगले 1-2 महीनों में इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, राज्य के लगभग 7,500 निवासियों को उचित मूल्य की दुकानें / राशन डिपो चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं के तेजी से वितरण में भी मदद मिलेगी।

महिला सशक्तिकरण और समाज कल्याण

126. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में अपनी गारंटियों को व्यवस्थित रूप से पूरा किया है। आज, हम उस चक्र को पूरा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पवित्र अवसर पर, अब भारत के इतिहास में सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा करने का समय आ गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कि कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब महिलाएं प्रगति करें, मुझे एक नई योजना, "मुख्य मंत्री मावां धीयां सतिकार योजना" के कार्यान्वयन की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जिसके तहत भगवंत मान सरकार सभी वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के लिए, भगवंत मान सरकार उनके खातों में सीधे 1,500 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी।

127. अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि यह भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की पहली यूनिवर्सल नकद हस्तांतरण योजना होगी। पंजाब की 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी, केवल कुछ को छोड़कर, अर्थात् मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी, जो भारत में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। यह पहल आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, घरेलू निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने और लड़कियों के बीच निरंतर शिक्षा और उच्च आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यह हमारे इस विश्वास की पुष्टि करता है कि सशक्तिकरण का प्रतिबिंब पंजाब भर की महिलाओं के लिए ठोस वित्तीय सुरक्षा और अधिक सम्मान के रूप में होना चाहिए।

128. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों ने ऐसी ही योजनाओं की घोषणा करने का जुमला तो छोड़ दिया है, लेकिन वे इसे महिलाओं के एक छोटे से वर्ग तक सीमित रखते हैं, जबकि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहता है, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे एक पड़ोसी राज्य ने ऐसी ही एक योजना की घोषणा की, लेकिन इसे केवल 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय

वाले परिवारों तक सीमित कर दिया, जिसमें सभी वयस्क महिलाओं की केवल 20% ही शामिल हो पाईं। लेकिन पंजाब ऐसे जुमले नहीं करेगा। माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी पंजाब की 20% महिलाओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि पंजाब की सभी महिलाओं के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए हमने यह सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बनने का फैसला किया है कि सभी वयस्क महिलाएं इस योजना के दायरे में आएं। तो चाहे वह कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी हो जिसे अतिरिक्त किताबों की जरूरत हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही बेटी हो जिसे कोचिंग की जरूरत हो, या फिर कोई महिला सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहती हो; या दादी अपनी पोती के लिए नया खिलौना खरीदना चाहती हो, अब उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका बड़ा भाई, उनका बेटा सरदार भगवंत सिंह मान हर महीने उनके बैंक खाते में 1000 से 1500 रुपये डालेगा। वित्त वर्ष 2026-27 में पारदर्शी और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 9,300 करोड़ रुपये का समर्पित बजटीय प्रावधान किया गया है।

129. इस प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, सरकार पूरे पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखेगी, जो गतिशीलता, पहुंच और अवसर का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। केवल पिछले साल में ही, महिलाओं द्वारा लगभग 12 करोड़ मुफ्त यात्राएं की गई हैं, जो इसकी व्यापक स्वीकार्यता और सामाजिक प्रभाव को दर्शाती हैं। इस सुविधा ने महिलाओं को वित्तीय बोझ के बिना काम, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए यात्रा करने में सक्षम बनाया है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

130. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना पंजाब के 155 एकीकृत बाल विकास सेवा ब्लॉकों में 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से समग्र बाल विकास के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करना जारी रखे हुए है। यह योजना लगभग 16.60 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं और प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 में, इस व्यापक पहुँच को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के लिए ₹932 करोड़ का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। ये आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण और प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण सामुदायिक मंचों के रूप में भी कार्य करते हैं।

131. नवंबर 2025 में, राज्य ने महिलाओं और किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य, गरिमा और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 'नवी दिशा योजना' शुरू की। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 13.65 लाख जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए 43 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसके तहत पूरे राज्य में हर महीने लगभग 1.2 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के सकारात्मक प्रतिसाद और बढ़ती पहुंच से प्रोत्साहित होकर, वित्त वर्ष 2026-27 में इस पहल को और मजबूत करने के लिए 65 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

132. समाज के कमजोर वर्गों को अपनी सहायता जारी रखते हुए, वित्त वर्ष 2026-27 में 36.52 लाख लाभार्थियों वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ₹6,150 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इन लाभार्थियों में बुजुर्ग, विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, आश्रित बच्चे और

दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

133. मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक कल्याण और न्याय क्षेत्र हेतु कुल ₹18,304 करोड़ का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित रखता हूं, जो इस क्षेत्र के कल्याणकारी उपायों के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। इसमें आशीर्वाद योजना के लिए ₹360 करोड़, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹261 करोड़ और आदर्श ग्राम योजना के लिए ₹75 करोड़ का आवंटन शामिल है, जिससे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी।

134. अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत 17,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो राज्य के कुल विकास परिव्यय का 35.23 प्रतिशत है।

राजस्व वृद्धि और पूंजी सृजन

135. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹1,26,190 करोड़ रहने का अनुमान है, जिसमें स्वयं के कर राजस्व का योगदान ₹70,851 करोड़ है और गैर-कर राजस्व ₹15,687 करोड़ निर्धारित किया गया है।

136. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि 16वें वित्त आयोग ने क्षैतिज वित्तीय हस्तांतरण में पंजाब की

हिस्सेदारी 1.807 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.996 प्रतिशत कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा वित्तीय वर्ष 2025-26 के ₹25,171 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बढ़कर ₹30,464 करोड़ होने का अनुमान है, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,293 करोड़ की वृद्धि होगी। भारत सरकार ने पांच वर्षों की अवार्ड अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से अनुदान सहायता ₹9,188 करोड़ रहने का अनुमान है।

137. हमने प्रत्येक प्रमुख राजस्व स्रोत में प्रभावशाली वृद्धि हासिल की है। आबकारी क्षेत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शासन की मंशा क्या है, इस से फ़र्क पड़ता है। पारदर्शी नीति, सख्त प्रवर्तन और लीकेज के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस के साथ, राजस्व प्राप्ति में काफी सुधार हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, आबकारी राजस्व ₹53,122 करोड़ होने का अनुमान है - जो पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल के ₹27,934 करोड़ और शिअद-भाजपा शासन के दौरान के ₹20,545 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

138. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व में वृद्धि केवल आबकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रही है। इसी तरह के सुधार स्टाम्प और पंजीकरण में भी दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान, स्टाम्प और पंजीकरण से प्राप्तियां ₹30,367 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान वास्तविक संग्रह ₹12,469 करोड़ और शिअद-भाजपा शासन के दौरान ₹12,387 करोड़ था। अब हमने

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

139. यह महज़ एक संख्यात्मक तुलना नहीं है; बल्कि यह दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। जब प्रणालियों को सख्त किया जाता है, विवेकाधिकार कम किया जाता है, और जवाबदेही लागू की जाती है, तो राज्य का वैध राजस्व जनता के खजाने में आता है, न कि अकुशलता या कदाचार में खो जाता है। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि प्रशासनिक दृढ़ संकल्प द्वारा समर्थित ईमानदार इरादा, सीधे तौर पर राज्य के लिए मजबूत वित्त और लोक भलाई में निवेश करने की अधिक क्षमता में परिवर्तित हो जाता है।

140. माननीय अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से लंबित पुराने विवादों को सुलझाने और करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2024 में ओटीएस नीति पेश की, जिसमें 70,311 डीलरों ने कुल 866 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त की और राजकोष ने 164 करोड़ रुपये की वसूली की।

141. उपरोक्त एकमुश्त निपटारा योजना की अनुसारता में सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी, एकमुश्त निपटारा योजना-2025 शुरू की है। यह योजना पात्र मामलों में ब्याज और दंड की पूर्ण छूट के साथ-साथ कर में स्तर-अनुसार राहत प्रदान करती है, जिससे व्यवसायों को पुराने मामलों को निपटाने और निश्चितता के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जा सके। व्यापार और उद्योग जगत से प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है, जिसमें अब तक 7,400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक ₹100 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई है। यह पहल हमारे संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाती है, अर्थात वास्तविक

करदाताओं को सुविधा प्रदान करना, साथ ही राजस्व प्राप्ति को मजबूत करना।

142. साथ ही, सरकार ने प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और खुफिया-आधारित प्रवर्तन का लाभ उठाकर जीएसटी प्रशासन में समेकित सुधार किए हैं। मल्टी-पोर्टल डेटा को एकीकृत करने और जोखिम का पता लगाने को स्वचालित करने के लिए एक आंतरिक विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित किया गया है, जिससे डिफॉल्टरों और कर चोरी की पहचान करके पर्याप्त वसूली हो रही है। केंद्रित निरीक्षणों और विशेष खुफिया, जांच और कानूनी क्षमताओं वाले एक समर्पित विरोधी-चोरी विंग के प्रस्तावित गठन के माध्यम से प्रवर्तन को और मजबूत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपालन में लगातार विस्तार और प्रवर्तन उपायों के समेकन से मजबूत होकर, हमने पिछले 46 महीनों में 83,739 करोड़ रुपये का जी.एस.टी. राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछली सरकार के 5 वर्षों में यह केवल 61,286 करोड़ रुपये था। यह हमारे कार्यकाल में कम्पनसेशन सैस से होने वाले राजस्व के नुकसान के बावजूद हासिल हुआ है। इस प्रभावशाली वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए, हमने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 32,000 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।

143. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय विवेक और दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन के उपाय के रूप में, राज्य ने समेकित परिशोधन निधि (सीएसएफ) में 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, और पहली बार, बोर्ड और निगमों को दी गई गारंटियों से उत्पन्न होने वाली आकस्मिक देनदारियों से राज्य की रक्षा के लिए गारंटी रिडेम्शन फ़ंड

(जीआरएफ) में अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है। इन योगदानों के साथ, सीएसएफ और जीआरएफ में राज्य के फंड में हमारी सरकार के दौरान 287% की वृद्धि हुई है, जो मार्च 2022 में 3,027 करोड़ रुपये से बढ़कर दिसंबर 2025 में 11,720 करोड़ रुपये हो गया है।

144. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के तहत राजस्व को मजबूत करने का उद्देश्य केवल बैलेंस शीट में सुधार लाना नहीं था — इसका उद्देश्य पंजाब की निर्माण क्षमता को बहाल करना था। वर्षों तक, पूंजीगत निवेश धीमा हो गया था जबकि देनदारियां बढ़ती जा रही थीं। हमने उस दृष्टिकोण को उलट दिया है। पिछले 4 वर्षों में हमारा कुल पूंजीगत व्यय 32,353 करोड़ रुपये है, जो पिछली सरकार की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। हमने इस वर्ष भी इसे और बढ़ाया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में, हमारी सरकार 18,381 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के परिव्यय का प्रस्ताव रखती है। यह एक सचेत विकल्प है: तात्कालिक (अस्थायी) खर्चों पर परिसंपत्ति निर्माण को प्राथमिकता देना, अल्पकालिक दिखावटी उपायों के स्थान पर पर दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देना, और उस बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना जो अगली पीढ़ी के काम आएगा।

145. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में की गई प्रतिबद्धता के अनुसार, हमारी सरकार ने 14,191 करोड़ रुपये की लिक्विडेशन प्लान का सम्मान किया है और छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन से उत्पन्न लंबित बकाया राशि जारी कर दी है, जो पिछली सरकार द्वारा अवैतनिक रह गई थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ये वैध भुगतान निर्धारित

कार्यक्रम के अनुसार पेंशनभोगियों को किए गए हैं, और हम वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस लिक्विडेशन प्लान के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान जारी रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

146. अंत में, अध्यक्ष महोदय, वित्तीय मज़बूती के हमारे प्रयासों ने पिछली सरकारों द्वारा राज्य पर छोड़े गए भारी कर्ज के बोझ को भी कम करना शुरू कर दिया है। 31 मार्च, 2022 तक हमारी सरकार को विरासत में 48.25% का कर्ज-से-जीएसडीपी अनुपात मिला था, जो 31 जनवरी, 2026 तक घटकर 44.47% हो गया है, जो किसी भी पैमाने पर एक महत्वपूर्ण गिरावट है।

निष्कर्ष

147. माननीय अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इसे पूरी जिम्मेदारी की भावना और अपने राज्य के भविष्य में अटूट विश्वास के साथ कर रहा हूँ। यह बजट उस यात्रा को दर्शाता है जिसे हमने पिछले चार वर्षों में तय किया है — एक ऐसी यात्रा जो पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और शासन में विश्वास को फिर से कायम करने पर केंद्रित है। इस सदन के समक्ष रखा गया प्रत्येक आवंटन और प्रत्येक सुधार एक स्पष्ट दृढ़ विश्वास के साथ रखा गया है: कि पंजाब की प्रगति टिकाऊ, समावेशी और मजबूत संस्थानों पर आधारित होनी चाहिए।

148. मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमें लगातार याद दिलाते हैं कि राजनीति ईमानदारी, जवाबदेही और आम नागरिक की सेवा में निहित होनी चाहिए। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, सरदार भगवंत सिंह मान जी के दृढ़ और जन-केंद्रित नेतृत्व के लिए भी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिनके स्पष्ट दृष्टिकोण और पंजाब की प्रगति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने इस सरकार के हर बड़े फैसले का मार्गदर्शन किया है। उनके मार्गदर्शन ने ईमानदारी से शासन करने और इस महान राज्य की उन्नति के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने के हमारे संकल्प को मजबूत किया है।

149. मैं वित्त और योजना विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके समर्पण और अथक प्रयासों ने इस व्यापक बजट को तैयार किया।

150. अब मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तावों को इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द